



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, १ नवम्बर, २०००

कार्तिक १०, १९२२ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—१

संख्या ३४६४/सह-वि-१—१ (क) २८-२०००

लखनऊ, १ नवम्बर, २०००

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २६० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, २००० पर दिनांक ३१ अक्टूबर, २००० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२ सन् २००० के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएं हत अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, २०००

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२ सन् २०००)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इच्छावन्तों के बीच में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, २००० कहा जायगा।

(२) यह ३० सितम्बर, २००० को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषाएँ

2—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा वापसित न हो,—

(क) "परिषद" का तात्पर्य द्वारा उक्त अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से है;

(ख) "केन्द्र" का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त स्टाफ शामिल है;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) "संस्था के प्रधान" का तात्पर्य उस संस्था के, अध्यापक, प्रचार्याचार्य या प्रधान अध्यापक से है;

(ङ) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है और इसके अन्तर्गत इस अध्यापन के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृम का नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(च) "संस्था" का तात्पर्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी किसी संस्कृत विद्यालय से है जिसमें उत्तर प्रदेश तक की संस्कृत शिक्षा दी जाती हो;

(छ) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे;

(ज) "मान्यता" का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिये प्राप्ति के लिये करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है;

(झ) "सम्भागीय संयुक्त निदेशक" का तात्पर्य किसी मन्त्रालय के प्रभारी शिक्षा संयुक्त निदेशक से है और इसमें सम्भागीय संयुक्त निदेशक के समस्त कर्तव्यों या उसमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ञ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ट) "केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है;

(ड) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि वह किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुचित साधन" का तात्पर्य प्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रेकार्ड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीफोन, याधरेण या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या युक्त के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

परिषद का संघटन

3--(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद स्थापित की जायगी।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) निदेशक, जो परिषद का अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो प्रधान;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो अध्यापक;

(घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक विज्ञान अध्यापक।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्राचार्य या विभागाध्यक्ष;

(च) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्कृत महाविद्यालयों के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो प्राचार्य;

(छ) राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित उक्त सभा के दो सदस्य;

(ज) राज्य के विज्ञान परिषद द्वारा निर्वाचित उक्त परिषद का एक सदस्य;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद;

(ञ) निदेशक, संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योग के दो प्रतिनिधि;

(ठ) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश;

(ड) प्राचार्य, केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबाद;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो उप निरीक्षक संस्कृत विद्यालय;

(ण) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलपति या उसका नाम निर्देशिनी जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो;

(त) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष;

(थ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ऐसा कोई अधिकारी, जो उप निदेशक शिक्षा से निम्न पंक्ति का न हो, जो सदस्य-सचिव होगा;

(द) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश;

(ध) उप निदेशक, संस्कृत, उत्तर प्रदेश।

(4) परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्भक्त रूप से गठन कब दिया गया है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

4--राज्य सरकार परिषद से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे परिषद के सदस्य के रूप में उसका बने रहना उचित के लिये हानिकार हो।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य का पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे शपथीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

5--(1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) परिषद का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायगा।

6--राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।

7--(1) परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन करने के

सदस्यों का हटाया जाना

सदस्यों की पदावधि

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना

परिषद की बैठक

लिये जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण-पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उप विधियों द्वारा की जाय।

(2) अध्यक्ष, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया परिषद का कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद की बैठक में उठने वाले सनत्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

8.—परिषद या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, परिषद या समिति में केवल किसी एक विद्यमान होने या उसके संकल्प से कोई मुक्ति होने के कारण अवधिमान्य नहीं होगी।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियाँ प्रविधिमान्य न होंगी

परिषद का कृष्य

9.—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथातः—

(क) संस्कृत शिक्षा में प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना;

(ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरा का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;—

(एक) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान किया गया हो; या

(दो) जो अध्यापक हों; या

(तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(घ) प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(ङ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(च) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(छ) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किये जायें;

(ज) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(झ) अन्य प्राध्यापकों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद अवधारित करे;

(ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति को बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(ट) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो;

(ठ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई माँगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें अपने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे, तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचाराधीन भेजना;

(ड) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों का करना जो उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक विकास के रूप में संघटित किए गये परिषद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो;

(ड) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन या कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक अथवा अनुपेक्षित हो।

10—(1) परिषद को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा दधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए; वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों।

परिषद के अधिकार

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद के निम्नलिखित अधिकार होंगे,—

(एक) किसी ऐसे अङ्गपूर्वी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वञ्चित कर देना, जिसे वह,—

- (क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का; या
- (ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का; या
- (ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरोध का; या
- (घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का; या
- (ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनीयता का,

दोषी पाये;

(दो) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या किसी कृत्यों के लिये या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद के किसी सदभावनापूर्ण मूल के कारण किसी अङ्गपूर्वी का परीक्षाफल रद्द करना;

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इनकार करना जो,—

(क) कर्मचारियों, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुँचती है; या

(ख) परिषद द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(पाँच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारियों, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिये परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद के सन्तोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(छ) नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों या निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिये मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो; और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट करना जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में पाठ्यक्रमों के लिये भर्ती किये जा सकें।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

11—धारा 10 के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी नये विषय या विषयों के वर्ग में या किसी उच्च कक्षा के लिये किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

किसी नये विषय में या उच्च कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

12—जहाँ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मान्य रूप से अनुसूचित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु

दान का उचित उपयोग

तब में, लिखा या प्रामाण्य किया जाता है, वेही इस प्रकार प्राप्त अभिलेखन या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायगा जिसके लिये वह संपत्ति को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अतन्त्र रूप से अनुरोधित संस्था को दान में सफल अभिलेखन या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायगा जिसका संज्ञाजन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश को अनुसार किया जायगा।

अधिनियम का
लक्ष्य होना

13--इस अधिनियम राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी बात को होत हुए भी, इस अधिनियम की प्रारम्भ की और से, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालयों सहित ऐसी सभी संस्थाएँ जो उत्तर मध्यम तक संस्कृत शिक्षा प्रदान कर रही हों और राजकीय संस्कृत विद्यालय, आश्रम या अनुसूचित संस्कृत विश्वविद्यालय, आश्रमों से सम्बन्ध या उनके द्वारा प्राप्यता प्राप्त हों इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा नियन्त्रित प्राप्ति समझी जायेंगी और उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बन्ध या उनके द्वारा साधना प्राप्त नहीं रह जायेंगी और इस अधिनियम को उपर्युक्तों से शासित होंगी :

प्रतिकल्प यह है कि उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व ऐसी संस्था में प्रयत्न, पूर्व मध्यम, या उत्तर मध्यम की पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों की परीक्षा लगा और उसे ऐसे व्यक्तियों को डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शक्ति होगी।

राज्य सरकार का
अधिकार

14--(1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सुचित करने का अधिकारी होगा।

(2) परिषद, राज्य सरकार को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा।

(3) यदि परिषद, उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(4) जब किसी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निदेश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विधिमतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार परिषद को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद के
अधिकारी और
अन्य कर्मचारी

15--इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ परिषद, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है।

परिषद के अध्यक्ष
के अधिकार और
कर्तव्य

16--(1) परिषद के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) परिषद के अध्यक्ष को परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधिवेशन पर जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।

(3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातक स्थिति में जिसमें उसके अध्यक्ष के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद को उसकी अगली बैठक में किये गये कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) परिषद का अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जायें।

17—परिषद् का सदस्य, परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए उसके विनिर्देशों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायें और विशेषतया, यह—

परिषद् के सदस्य के अधिकार और कर्तव्य

(क) वापिक प्राकमलन और लेखा-विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियाँ उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जायें जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रविष्ट की गयी हैं;

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यसूचि रखने के लिए उत्तरदायी होगा; और

(घ) परीक्षाओं के आयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों।

(ङ) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18—(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए ऐसी निम्नलिखित समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात् :—

समितियों और उप समितियों की नियुक्ति और संघटन

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति।

(2) ऐसी समितियों में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे, और इनका गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासंभव निम्नलिखित वर्गों में से इष्टतम व्यक्तियों के एक-एक सदस्य की प्रतिनिधित्व दिया जा सके :—

(क) संस्थाओं के प्रधानाचार्यों का प्रभाव,

(ख) अध्यापक;

(ग) राज्य की विधान सभा के सदस्य,

(घ) राज्य की विधान परिषद् के सदस्य,

(ङ) शिक्षाविद्।

प्रतिबंध यह है कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद् की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, परिषद् ऐसी अन्य समितियाँ या उप समितियाँ, जो विनियमों द्वारा विहित की जायें, नियुक्त कर सकती है।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उप समितियों का गठन ऐसी शक्ति से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19—परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने के अधिकार के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य किसी अधिकार का प्रयोग सभापति या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जायें, किया जा सकता है।

प्रस्तावों का अधिकार

20—केन्द्र प्रवीक्षक और अन्तरीक्षक भारतीय इण्ड संहिता की धारा 21 के अधीनस्थ लोक सेवक समझे जायेंगे।

केन्द्र प्रवीक्षक और अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे

21—(1) परिषद् इस अधिनियम के उपधाराओं को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

परिषद् का विनियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थात् :—

(क) समितियों और उप समितियों का संघटन उनके अधिकार और कर्तव्य;

(207)

- (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र का प्रदान करना;
- (ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें;
- (घ) समस्त प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
- (ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अध्यर्थी परिषद की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे;
- (च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन;
- (ज) परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र परिष्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें;
- (झ) मान्यता के विद्योपाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लेना;
- (ञ) ऐसे नमस्त-विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाती हो या की जा सके।

परिषद द्वारा
बनाए गए
विनियमों का
प्रकाशन और
पूर्व अनुमोदन
प्रशासन योजना

22—(1) धारा 21 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाए जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार सहित या परिष्कार रहित अनुमोदित कर सकती है।

23—(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और उसके दो अध्यापक, जो उच्चता के अनुसार बारी-बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के संबंध में प्रबन्ध समिति के अलग-अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अध्यावेदन पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

(7) जब भी किसी संस्था के प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो ऐसे व्यक्ति से; जिसका सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जैसी वह उचित समझे ऐसी संस्था के कार्यकर्ताओं पर वास्तविक नियन्त्रण पाया जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन की तब तक मान्यता प्रदान की जायगी जब तक कि सभ्य अधिकारिता को कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, विरोधी दावेदारों को लिखित अवकाश देने का सुविशुद्ध प्रवर्तन करेगा :

स्पष्टीकरण:—इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था पर वास्तविक नियन्त्रण किसका है, सम्भागीय संयुक्त निदेशक संस्था की निधि और उसके प्रशासन पर नियन्त्रण, उसकी सम्पत्ति से साध की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुचित प्रशासन की शक्त और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

24—(1) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाओं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उन्नाव, संस्कृत पाठशालाओं (सम्भागीय) जमीन अधिकारिता के अधीन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी होंगे :

(2) निदेशक, उप निदेशक, संस्कृत और सम्भागीय संयुक्त निदेशक या उसकी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या उसका निरीक्षण करा सकता है ।

(3) निदेशक, निरीक्षण के समय या अन्य प्रकार से पावी नहीं किसी भूति या कमी का निराकरण करने के लिए संस्था के प्रबन्धन को निदेश दे सकता है ।

(4) यदि प्रबन्धन उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहे तो निदेशक, प्रबन्धन द्वारा दिये गये किसी समीक्षा या अवकाश पर, यदि कोई हो, विचार करने के परावर्त,--

(क) सामग्री वापस लेने के लिए सामग्री को परिवर्त के पास अतिविष्ट कर सकता है; या

(ख) उपधारा (3) के अधीन संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है ।

(5) यदि उपधारा (4) के खण्ड (क) में अतिविष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकता है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवाजित कर संस्था का प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसके निहित भूमि, भवन, निधि और अन्य परिश्रमपत्तियां भी हैं, अपने हाथ में ले सकता है, और कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निर्देशनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति की होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्रथमतः एक वर्ष के अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर है तो वह समय-समय पर आदेश के प्रवर्तन की एक बार में एक वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अन्यतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति विधिपूर्वक संघटित हो गयी है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उपधारा (5) या इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी समय विच्छिन्न कर सकती है ।

संस्थाओं पर
निरीक्षण और
दावे का हल
किया जाय

(7) कोई अधिकृत नियंत्रक सॉफ्ट गैस कतलॉग का पालन करने में अपने हाथ मद्ध-
भावना से किये गये कृत्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा।

(8) उपरान्त (5) के अधीन दिया गया कोई आवेदन संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है, से सम्बन्धित या संस्था की या उसमें निहित किसी प्रवृत्ति से सम्बन्धित किसी आय प्रतिनिधिमिति या समितिके सदस्यपदों की नियुक्ति या अवनियुक्ति होने पर भी प्रभावी होने।

(5) उपधारा (4) के अन्तर्गत (क) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रत्येक नगरपालिका को निम्नलिखित कार्य कराने होंगे—

(२०) इस आरादाय भारत सरकार के द्वारा १९५०-५१ के बजट में १० लाख रुपये का अनुदान दिया गया था।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

THE
NEW
AND
REVISED
EDITION

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णाय नमः
 श्रीगुरुभ्यो नमः
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीसूर्याय नमः

[illegible]

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदात किये गये अधिकारों की व्यावहारिक प्रवृत्ति प्रभाव लक्ष्य दिनांकितियों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:-

- (क) आचार संहिता, परिचीना की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा पदोन्नति के प्रक्रिया और शर्तें, जिसमें अन्तर्गत जाँच या अपेक्षित जाँच होने तक या नैतिक पक्ष पर सत्यनिष्ठा किट्टी अपराध के लिए किसी दण्डिक मामले में सम्मेलन, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बित की है तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियाँ और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित हैं;
- (ख) वेतन क्रम और वेतनों का भुगतान;
- (ग) एक मासिकता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण;
- (घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ; और
- (ङ) कार्य और सेवा के अमिलेख का रखा जाना ।

(3) (क) संस्था का कोई प्रधान या अध्यापक, सम्भागीय संयुक्त निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुखित किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकता है न पदच्युत किया जा सकता है और न ही उसकी उपस्थितियों में कोई कमी की जा सकती है और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकता है।

(ब) सभागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने के नॉटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में सम्मागीय संयुक्त निदेशक आदेश जारी करने के पूर्व संस्था के प्रधान या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देना कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतावे कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी सम्भागीय संयुक्त निदेशक को आदेश को विरुद्ध आदेश की सूचना पाने के दिनों से एक माह के भीतर निदेशक के समक्ष अपनी प्रस्तुत कर सकता है और निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द या परिष्कृत कर सकता है और निदेशक का आदेश अन्तिम होता ।

(4) किसी संस्था का प्रधान या अध्यक्ष प्रत्यक्षतः द्वारा नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि प्रत्यक्षतः की राय में,—

(क) उसके विरुद्ध आरोप होने सम्भवी न हों कि उसने उसकी पदभूमि करना, पद छोड़ना या पदच्युत करना उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर होने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विधायक मामला अन्वेषण, जांच या दण्ड के अधीन है, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो।

(5) जब कभी प्रत्यक्ष समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यक्ष नियुक्त किया जाय तो उसकी सूचना निलम्बन के आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर सम्भागीय संयुक्त निदेश की सी जायगी और सूचना के साथ ऐसे विवरण भी विनियमों द्वारा विहित किए जायेंगे जिनमें और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।

(6) निलम्बन का कोई आदेश जब तक कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित रूप में सुमोहित न हो उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और सम्भागीय संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी अपील में आपत्ति नहीं की जायगी।

(7) यदि किसी समय सम्भागीय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यक्ष के किसी दोष के बिना विरुद्ध किया जा रहा है तो सम्भागीय संयुक्त निदेशक प्रत्यक्षतः की अपराधोद्घरण देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गये निलम्बन के आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता है।

27—परिषद् या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति व्यावहार्य सीमा उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी अकस्मिक रिक्ति में निर्दिष्ट या नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस दोष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो।

आकस्मिक
रिक्तियों

28—(1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती हैं, जिनमें,—

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गजपति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके;

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियां से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

परिषद् और
समितियों का रूप-
विधियां बनाने का
अधिकार

(2) परिषद् और उसकी समितियां परिषद् या समिति के सदस्यों को परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और उनमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेंगी।

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गयी किसी उपविधि में संशोधन या विवरण देने का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी।

29—राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति और उपसमिति या परिषद् या किसी समिति या उपसमिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अनियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये किसी नियम, विनियम, उपविधि, दिये गये आदेश या निदेश के अनुसरण में सम्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।

सम्भावना से किए
गए कार्य के लिए
संरक्षण

30—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रवृत्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

न्यायालयों के
अधिकार क्षेत्र
पर रोक

31—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी सुगतान उसी में किये जायेंगे।

परिषद् की निधि

(2) राज्य सरकार को किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उपबन्धों या प्रयोजनों के लिए ऐसी बनरालि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा और लेखा
परीक्षा

32—(1) परिषद्, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रवन्ध में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे अधिक लेखा विवरण पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनाय प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् को लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा पर्याप्तमानित परिषद् को दोगे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार की प्रतिकृति भेजे जायेंगे।

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति

33—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उप-धारा (1) के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर समी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

नियम बनाने
की शक्ति

34—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और
अपवाद

35—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2000 एच.आर.आर. निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सदा सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
सद्व 2000

आशा से,

योगेन्द्र राम सिवाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 2464 (2)/XVII-Y-1—1 (KA) 28-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 343 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000:

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION ACT, 2000

(U. P. ACT No. 32 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for the establishment of a Board of Secondary Sanskrit Education in the State and for the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 30, 2000.

(212)

2. In this Act unless the context otherwise requires;

Definition

(a) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education established under section 3;

(b) "Centre" means an institution or a place fixed by the Board for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto;

(c) "Director" means the Director of Secondary Education, Uttar Pradesh;

(d) "Head of the Institution" means the Principal or the Head Master, as the case may be of that institution;

(e) "Inspector" means the district Inspector of Schools and includes an Officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Ordinance;

(f) "Institution" means a sanskrit school imparting sanskrit education upto Uttar Madhyama recognised by the Board;

(g) "Invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations, at a Centre;

(h) "Recognition" means recognition for the purpose of preparing candidates for admission to the Board's Examination;

(i) "Regional Joint Director" means the Joint Director of Education in charge of a region and includes an officer authorised by the State Government to perform all or any of the duties of a Regional Joint Director;

(j) "regulation" means regulations made under this Act;

(k) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent;

(l) "Unfair means" in relation to an examinee while answering questions in an examination, means the unauthorised help from any person directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorised telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint, there shall be established a Board to be known as the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education.

Constitution of the Board

(2) The Board shall be a body corporate.

(3) The Board shall consist of the following members namely:—

(a) the Director, who shall be the Chairman of the Board;

(b) two Heads of the Institutions maintained by the State Government, nominated by the State Government;

(c) two teachers of the Institutions maintained by the State Government, nominated by the State Government;

(d) one Science teacher of any degree college affiliated to Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, nominated by the State Government;

(e) one Principal or Head of the Department of an Ayurvedic Medical College maintained by the State Government, nominated by the State Government;

(f) two Principals of Sanskrit degree colleges maintained by the State Government, nominated by the State Government;

(g) two members of the Legislative Assembly of the State elected by the said Assembly;

(213)

(h) one member of the Legislative Council of the State elected by the said Council ;

(i) three academicians, nominated by the State Government ;

(j) Director, Sanskrit Academy, Uttar Pradesh ;

(k) two representatives of industries nominated by the State Government ;

(l) Director, State Institute of Science Education, Uttar Pradesh ;

(m) Principal, Central Pedagogical Institute, Allahabad ;

(n) two Deputy Inspectors of Sanskrit Schools nominated by the State Government ;

(o) Vice-chancellor of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi or his nominee, not below the rank of Reader ;

(p) two Heads of the departments of Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, nominated by the State Government ;

(q) an officer not below the rank of Deputy Director of Education nominated by the State Government who shall be the Member-Secretary ;

(r) Inspector, Sanskrit Pathshalayen, Uttar Pradesh.

(s) Deputy Director, Sanskrit, Uttar Pradesh.

(4) As soon as may be after the election and nomination of the member of the Board have completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted :

Provided that a notification under this sub-section may be issued even before the election of the members specified in clause (g) or clause (h) of sub-section (3) has been completed.

Removal of members

4. The State Government may remove from the Board a member other than an *ex-officio* member, who in its opinion, has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest:

Provided that the State Government shall, before removing a member as aforesaid, give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal.

Terms of Office of members

5. (1) A member other than *ex-officio* member, shall hold office for a term of three years from the date of the notification under sub section (4) of section (3) :

Provided that the State Government may, by notification enlarge the term of the office of all such members by a period not exceeding six months at a time, so however that the enlargements so granted shall not in the aggregate exceed one year.

(2) A member of the Board shall cease to be such member upon his ceasing to have the capacity in which he was elected or nominated, and his seat shall thereupon, become vacant.

Filling of vacancies on expiry of term of office

6. The State Government shall take steps for the reconstitution of the board before the expiry of the term of office of members under section (5).

Meetings of the Board

7. (1) The Board shall meet at such time and place and shall subject to the provisions of sub-sections (2) and (3) observe such procedure in transacting the business at its meetings, including the quorum thereat, as may be provided by bye-laws made in this behalf.

(2) The Chairman shall preside at the meeting of the Board. In his absence, any member of the Board chosen by its members present at the meeting shall preside at the meeting.

(3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members present and voting and

(214)

in case of equality of votes, the person presiding at such meeting shall have a second or casting vote.

8. No act or proceedings of the Board or of a committee appointed by it, shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Board or the committee.

Vacancies etc.
not to invali-
date acts and
proceedings

9. Subject to the other provisions of this Act, the Board shall have the following powers namely:—

Functions of
the Board

(a) to prescribe course of instructions, text-books other books and instructional material, if any, for Prathama, Madhyama and Uttar Madhyama classes in sanskrit education;

(b) to publish or manufacture, whether to the exclusion, complete or partial of others or otherwise, all or any such text-books, other books or instructional material;

(c) to grant diplomas or certificates to persons, who-

(i) have pursued a course of study in an institution admitted to the privileges or recognition by the Board;

(ii) are teachers; or

(iii) have studied privately under conditions laid down in the regulations and have passed an examination of the Board under like conditions;

(d) to conduct examinations at the end of the Prathama, Parva-Madhyama, and Uttar Madhyama Courses;

(e) to recognise institutions for the purposes of its examination;

(f) to admit candidates to its examination;

(g) to demand and receive such fee as may be prescribed in the regulations;

(h) to publish or withhold publication of the results of its examinations wholly or in part;

(i) to co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine;

(j) to call for reports from the Director on the condition of recognised institutions or of institutions applying for recognition;

(k) to submit to the State Government its views on any matter with which it is concerned;

(l) to see the schedules of new demands proposed to be included in the budget relating to institutions recognised by it and to submit if it thinks fit, its views thereon for the consideration of the State Government;

(m) to do all such other acts and things as may be requisite in order to further the objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising sanskrit education upto Uttar Madhyama;

(n) to take all such steps as may be necessary or convenient for or may be incidental to, the exercise of any power, or the discharge of any function or duty, conferred or imposed on it by this Act.

10. (1) The Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, have all such powers as may be necessary for the discharge of its functions and the performance of its duties under this Act, or the rules or regulations made thereunder.

Powers of the
Board

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall have the powers,—

(i) to cancel an examination or withhold the result of an examination of a candidate, or to disallow him from appearing at any future examination who is found by it to be guilty of,—

(a) using unfair means in the examination; or

(25)

(b) making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the examination; or

(c) fraud or impersonation at the examination; or

(d) securing admission to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination; or

(e) any act of gross indiscipline in the course of the examination;

(ii) to cancel the result of an examination of any candidate for all or any of the acts mentioned in sub-clauses (a) to (e) of clause (i) or for any bonafide error of the Board in the declaration of the result;

(iii) to prescribe fees for the examinations conducted by it and provide for the manner of their realisation;

(iv) to refuse recognition of an institution,—

(a) which does not fulfil, or is not in a position to fulfil, or does not come up to the standards for staff, instructions, equipment or buildings laid down by the Board in this behalf; or

(b) which does not, or is not, willing to abide by the conditions of recognition laid down by the Board in this behalf;

(v) to withdraw recognition of an institution not able to adhere to, or make provisions for, standards of staff, instructions, equipment or buildings laid down by the Board or on its failure to observe the conditions of recognition to the satisfaction of the Board;

(vi) to call for reports from the Heads of recognised institutions in respect of any act of contravention of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, and take suitable actions for the enforcement of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, in such manner as may be prescribed by regulations;

(vii) to inspect an recognized institution for the purpose of ensuring due observance of the prescribed courses of study and that facilities for instructions are duly provided and availed of; and

(viii) to fix the maximum number of students that may be admitted to courses of study in a recognized institution.

(3) The decision of the Board in all matters mentioned in sub-sections (1) and (2) shall be final.

Recognition of
an institution in
any new subject
or for a higher
class

11. Notwithstanding anything contained in clause (a) of section 10, the Board may, with the prior approval of the State Government, recognise an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class.

Proper utilization of donation

12. Where a contribution or donation, either in cash or in kind, is taken or received by an institution including an institution maintained exclusively by the State Government, or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of an institution maintained exclusively by the State Government, the cash contribution or donation shall be credited to personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with general or special orders of the State Government.

Application of
the Act

13. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or any other Uttar Pradesh Act, on and from the commencement of this Act, all the institutions, situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting sanskrit education upto Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by the Government Sanskrit College, Varanasi or Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Board under this Act and shall cease to be affiliated to or recognised by the said Government college or Vishwavidyalaya and shall be governed by the provisions of this Act;

Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before such commencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons.

14. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to any work conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

Power of the State Government

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it is proposed to be or has been taken upon its communication.

(3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.

(4) Whenever, in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient to take immediate action, it may, without making any reference to the Board under the foregoing provisions, pass such order or take such other action consistent with this Act as it deems necessary, and in particular, may by such order modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall forthwith inform the Board accordingly.

(5) No action taken by the State Government under sub-section (4) shall be called in question.

15. For the purpose of enabling it efficiently to discharge its functions under this Act, the Board may appoint such number of officers and other employees as it may, with the previous approval of the State Government, think fit.

Officer and other employees of the Board

16. (1) It shall be the duty of the Chairman of the Board to see that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

Powers and duties of the Chairman of the Board

(2) The Chairman of the Board shall have power to convene meetings of the Board and shall call a meeting, at any time after due notice, on a requisition signed by not less than one fourth of the total Membership of the Board and stating the business to be brought before the meeting.

(3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Board, which in the opinion of its Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report the action taken to the Board at its next meeting.

(4) The Chairman of the Board shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

17. The Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by rules, and in particular,—

Powers and duties of the Secretary of the Board

(a) be responsible to prepare and present the annual estimates and statement of accounts;

(b) be responsible to ensure that all moneys are spent for the purposes for which they are granted or allotted;

(c) be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board;

(d) shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the examinations; and

(217)

(e) shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

Appointment
and constitution
of Committees
and Sub-com-
mittees

18. (1) The Board shall appoint the following committees and different committees may be appointed for different areas of the State, namely,—

- (a) Curriculum Committee;
- (b) Examinations Committee;
- (c) Results Committee;
- (d) Recognition Committee; and
- (e) Finance Committee.

(2) Such committees shall consist of the Members of the Board only and shall be constituted in such a way that as far as possible atleast one Member from each of the following classes are represented in each of the committees:-

- (a) Principal or Head of Institutions;
- (b) Teachers;
- (c) Member of the Legislative Assembly of the State;
- (d) Member of the Legislative Council of the State;
- (e) Academicians;

Provided that no Member of the Board shall serve on more than one of such committees, and the term of Members of the committee shall cease with the cessation of Membership of the Board.

(3) In addition to the committees mentioned in sub-section (1) the Board may appoint such other committees or sub-committees as may be prescribed by regulations.

(4) The committees and sub-committees appointed under sub-section (3) shall be constituted in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by regulations.

Power to
delegate

19. The Board may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make regulations may also be exercised by its Chairman or by such Committee or officer in such cases and subject to such conditions, as may be specified therein.

Superintendent
of a centre and
invigilator to be
public servant

20. (1) The Superintendent of a Centre and an invigilator shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Power of the
Board to make
regulations

21. (1) The Board may make regulations for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters, namely:—

- (a) constitution, powers and duties of committees and sub-committees;
- (b) the conferment of diplomas and certificates;
- (c) the conditions of recognition of institutions;
- (d) the courses of study to be laid down for all certificates and diplomas.
- (e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas and certificates;
- (f) the fees for admission to the examination of the Board;
- (g) the conduct of examinations;

(h) the appointment of examiners, moderators, collators, scrutini-
sers, tabulators, centre inspectors, Superintendents of Centres and
invigilators and their duties and Powers in relation to the Board's
examinations and the rates of their remuneration;

(i) the admission of institutions to the privileges of recognition
and the withdrawal of recognition;

(j) all matters which are to be, or may be, provided for by regu-
lations.

22. (1) Regulations under section 21 shall be made only with the
previous approval of the State Government and shall be published in the
Gazette.

Publication and
previous approval
of regulations
made by the
Board

(2) The State Government may approve any such regulation proposed
by the Board with or without modification.

23. (1) Notwithstanding anything contained in any law, document
or decree or order of a court or other instrument, there shall be a
Scheme of Administration for every institution, whether recognised
before or after the commencement of this Act. The Scheme of Adminis-
tration shall amongst other matter provide for the constitution of a
Committee of Management vested with authority to manage and conduct
the affairs of the institution. The Head of the institution and two
teachers thereof, who shall be selected by rotation according to seniority
in the manner to be prescribed by regulations, shall be *ex-officio* members
of the Committee of Management with a right to vote.

Scheme of
Administration

(2) No member of the Committee of the Management shall either
attend the meeting of the Committee or exercise his right to vote whenever
a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(3) The Scheme of Administration shall also describe subject to any
regulation, the respective powers, duties and functions of the Head of the
institution and Committee of Management in relation to the institution.

(4) Where more than one recognised institutions are maintained by
a body or authority there shall be separate Committee of Management
for each institution unless otherwise provided in the regulations for any
class of institutions.

(5) The Scheme of Administration of every institution shall be
subject to the approval of the Director and no amendment to, or change
in, the Scheme of Administration shall be made at any time without the
prior approval of the Director:

Provided that where the Management of an institution is aggrieved
by an order of the Director refusing to approve an amendment or change
in the Scheme of Administration, the State Government, on the represen-
tation of the Management, may, if it is satisfied that the proposed
amendment or change in the Scheme of Administration is in the interest
of the institution, order the Director to approve the same, and thereupon
the Director shall act accordingly.

(6) Every recognised institution shall be managed in accordance with
the Scheme of Administration framed under and in accordance with,
sub-section (1) to sub-section (5).

(7) Whenever there is a dispute with respect to the Management of
an institution, persons found by the Regional Joint Director upon such
enquiry as he deemes fit, to be in actual control of its affairs may, for the
purposes of this Act be recognized to constitute the Committee of
Management of such institution until a court of competent jurisdiction
directs otherwise:

Provided that the Regional Joint Director shall before making an
order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival
claimants to made representations in writing.

Explanation: In determining the question as to who is in actual
control of the affairs of the institutions the Regional Joint Director shall
have regard to the control over the funds of the institution and over the

Inspection of
institutions and
removal of defects

administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under sub-section (5) and other relevant circumstances.

24. (1) Inspector, Sanskrit Pathshalayan, Uttar Pradesh, Allahabad or Deputy Inspector, Sanskrit Pathshalayan (Regional), shall be competent authority for the inspection of institutions within his jurisdiction.

(2) The Director, Deputy Director, Sanskrit and Regional Joint Director or any officer authorised by him may also inspect an institution or cause the same to be inspected.

(3) The Director may direct the Management of an institution to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

(4) Where the Management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may, after considering the explanation or representation, if any, given by the Management,—

(a) refer the case to the Board for withdrawal of recognition; or

(b) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (5).

(5) If on receipt of a recommendation referred to in clause (b) of sub-section (4) the State Government is satisfied that in the interest of the institution it is necessary that the Management of that institution be handed over to an Authorised Controller, the State Government may, by order, for such period as may be specified in the order, appoint an authorised Controller, and the Authorised Controller, may take over the Management of the institution including Management of the land, building, funds and other assets belonging to or vested in the institution to the exclusion of the Committee of Management or any other person, and whenever the Authorised Controller so takes over the Management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose have, in relation to the Management of the institution, all such powers and authority as the Committee of Management would have if no order were made under this sub-section.

(6) An order under sub-section (5) shall be operative for a period not exceeding one year in the first instance:

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution it may from time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time as it may specify, so however that the total period of operation of the order including the period specified in the initial order under sub-section (5) does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorised Controller shall continue to function as such until the State Government is satisfied that the Committee of Management has been lawfully constituted:

Provided also that the State Government may at any time revoke an order made under sub-section (5) or under this sub-section.

(7) No Authorised Controller shall be personally liable for acts done by him, in good faith, in performance of duties entrusted to him.

(8) Any order made under sub-section (5) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument, relating to the Management and control of the institution, including any scheme of Administration, or relating to the property belonging to or vested in the institution.

(9) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (a) of sub-section (4) and no order made under sub-section (5) shall be called in question in any court.

(10) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of, any powers conferred on the State Government or the Authorised Controller under any other law for the time being in force.

25. Subject to the provisions of this Act, the Head of institution and teachers and other employees of an institution shall be appointed in accordance with the regulations.

Procedure for appointment of Head of institution, teachers and other employees

26. (1) Every person employed in an institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by regulations and any agreement between the Management and such employees in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the regulations, shall be void.

Conditions of Service of Head of institution, teachers and other employees

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the regulations may provide for,—

(a) the code of conduct, the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency of investigation, inquiry or trial in any criminal case for an offence involving moral turpitude and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice;

(b) the scales of pay and payment of salaries;

(c) transfer of service from one recognized institution to another;

(d) grant of leave and provident fund and other benefits; and

(e) maintenance of record of work and service.

(3) (a) No Head of institution or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Regional Joint Director.

(b) Regional Joint Director may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management:

Provided that in the cases of punishment, before passing order, the Regional Joint Director shall give, an opportunity to the Head of institution or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

(c) Any party may prefer an appeal to the Director against an order of the Regional Joint Director under clause (b) within one month from the date of communication of the order to that party and the Director may, after such further enquiry as he considers necessary, confirm, set-aside or modify the order and the order passed by the Director shall be final.

(4) No Head of institution or teacher shall be suspended by the Management, unless in the opinion of the Management,—

(a) the charges against him are serious enough to merit his dismissal, removal or reduction in rank; or

(b) his continuance in office is likely to hamper or prejudice the conduct of disciplinary proceedings against him; or

(c) any criminal case for an offence involving moral turpitude against him is under investigation, enquiry or trial.

(5) Where any Head of institution or teacher is suspended by the Committee of Management it shall be reported to the Regional Joint Director within seven days from the date of order of suspension and the report shall contain such particulars as may be prescribed by regulations and accompanied by all relevant documents.

(6) No such order of suspension shall, unless approved in writing by the Regional Joint Director, remain in force for more than sixty days from the date of such order and the order of the Regional Joint Director shall be final and shall not be questioned in any court.

(7) If at any time the Regional Joint Director is satisfied that disciplinary proceedings against the Head of institution or teacher are being delayed for no fault of the Head of institution or the teacher, the Regional Joint Director may after affording opportunity to the Management to make representation, revoke an order of suspension passed under this section.

**Casual
Vacancies**

27. All casual vacancies among the Members, other than *ex-officio* Members, of the Board or of a Committee appointed by the Board, shall be filled, as soon as may be, by the person or body who elected, or nominated the member whose place has become vacant and the person elected or nominated to a casual vacancy shall be a member of the Board or Committee for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

**Power of the
Board and Com-
mittee to make
bye-laws**

28. (1) The Board and its Committees may make bye-laws consistent with this Act the rules and the regulations,—

(a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(b) providing for all matters which are to be, or may be, provided for by bye-laws;

(c) providing for all matters solely concerning the Board and its Committees and not provided for by this Act the rules and the regulations.

(2) The Board and its Committees shall make bye-laws providing for the giving of notice, to the members of the Board or Committee, of the dates of meeting of the Board or Committee, and of the business to be considered at meetings, and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Board may direct amendment or recession of any bye-law made by a Committee under this section and the Committee shall give effect to any such direction.

**Protection for
acts done in good
faith**

29. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Board or any of its Committees and sub-committees or any member of the Board or a Committee or sub-committee or any other person in respect of any thing, which is, in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation, bye-law, order or direction made thereunder.

**Bar of Juris-
diction of courts**

30. No order or decision made by the Board or any of its committees or sub-committees in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

**Fund of the
Board**

31. (1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the Board shall be credited thereto and all payments for the Board shall be made therefrom.

(2) Subject to any general or special order of the State Government, and subject to the provisions of this Act, the Board shall have the power to spend such sum as it may think fit on subjects or for purposes authorised by this Act.

**Accounts and
audit**

32. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as the State Government may, by general or special order, specify.

(2) The Board shall prepare an annual financial statement and submit it to the State Government for its approval.

(3) The accounts of the Board shall be audited by such authority as the State Government may, by general or special order, specify.

(4) The accounts of the Board as certified by the audit authority together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government.

33. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

Power to remove difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

34. The State Government may by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

35. (1) The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Ordinance, 2000 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

U. P.
Ordinance
No. 15 of
2000

By order,
Y. R. TRIFATHI,
Pramukh Sachiv,